(b) The procurement price of wheat during the years 1984-85 to 1988-89 had been as under:

Year	Procurement price (Rs. per quintal)
1984-85	152
1985-86	157
1986-87	162
1987-88	166
1988-89	173

The procurement price of wheat for the year 1989-90 has been fixed as Rs. 183 per quintal.

बीज सम्बन्धी आयात नीति का निर्धारण

2733. **श्री शरद यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार बीज संबंधी आयात नीति किस तरह निर्धारित करती है;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या-क्या जिन्हें बीज संबंधी आयात-नीति के निर्धारण का काम सौंपा गया है और वे किस-किस क्षेत्र में संबंधित है; और

(ग) क्या यह सच है कि कृषि वैज्ञानिकों ने चालू बीज तथा नई बीज नीति के संबंध में अपना असंतोष व्यक्त किया है और यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) कृषि मंत्रालय विभिन्न अन्य मंत्रालयों के परामर्श से बीजों के आयात संबंधी नीति निर्धारण करता है इसकी घोषणा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाती है ।

(ख) बीजों के आयात संबंधी नीति निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम बताया जाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा ।

(ग) जी, नहीं ।

प्रबंध कार्य में मजदूरों की भागीदारी

2734. **श्री शरद यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उद्योग के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के मुद्दे पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के मुद्दे पर पहले भी विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित पहले की योजना का क्या हुआ और उसे अब तक लागू न करने के क्या कारण रहे थे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकृष्ण मालवीय) : (क) प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी की एक व्यापक योजना को इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 के संकल्प सं० एल-56011/1/83-डस्क-I (बी) के तहत अधिसूचित किया गया था । यह योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) योजना के ब्यौरे दर्शाने वाली प्रतिलिपी अनुबंध में दी गई है [देखिये परिशिष्ट 149, अनुबंध सं० 146] ।

(ग) और (घ) पहले 30 अक्तूबर, 1975 को तथा पुनः जनवरी 1977 में प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी की योजनाओं को अधिसूचित किया गया था । 1975 की योजना विनिर्माण तथा खनन क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए थी जबकि 1977 की योजना वाणिज्यिक तथा सेवा संगठनों में कार्यान्वयन के लिए थी । इन योजनाओं के कार्यकरण की पुनरीक्षा की गई थी और